(ii) Nutritional status of the population.

(iii) Health status, mortality, morbidity, assess to and use of health services (public and private) and costs

(iv) Educational status, school enrolment by region, sex and age group and by economic-social classes, reach and quality of public education services and costs.

(v) Living environments distribution by density of settlement. Living space per head, type of houses; access to safe drinking water and sanitation; access to amenities.

(10) The first information indicator provided by the poverty ratio under this methodology needs to be supplemented and corrected with other indicators—which may also be more readily verifiable than income or consumption expenditure. This is important in order to refine targetting so that the ineligible are excluded from and the eligible are fully covered in the intended benefits from targetted anti-poverty programmes.

मध्य प्रदेश में केन्द्रीय निवेश

2472. **श्री अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 1988-89 की तुलना में वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय पूंजी निवेश में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश का अनुपात पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना रहा है ; और

(घ) मध्य प्रदेश में केन्द्रीय पूंजी निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार रखती है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) केन्द्रीय योजना निवेश राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए देश के लिए समग्र रूप से किया जाता है। राज्यवार यह न तो आयोजित होता है और न ही इसकी गणना की जाती है।

(घ) आठवीं योजना के लिए निर्दिष्ट प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव जब भी प्राप्त होंगे, गुण दोष तथा राज्य की आवश्यकता के आधार पर विचार किया जायेगा।

राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये वित्तीय सहायता

2473. **श्री अजीत जोगी :**

चौधरी हरि सिंह :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता देने का विचार रखती हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस धनराशि को वितरित करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या मानदंड अपनाये गये हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य-वार कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम;

(ख) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीणयुवाओं को प्रशिक्षण

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

(घ) जवाहर रोजगार योजना ; (ङ) मरुस्थल विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसी स्कीमों को सहायता प्रदान की जा रही है ;

(ग) स्कीम दर स्कीम मानदंड भिन्न-भिन्न हैं, जो वृहद कार्यक्रम जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाते हैं तथा जिनके लिए राज्यों को सहायता दी जाती है, ये हैं; एकीकृत